

20% EXTRA
वांधनी हिंग तड़का हिंग
5g, 10g, 20g, 50g, ₹ 100g में उपलब्ध
SIBROCHI SPICES PVT. LTD. NAGPUR, Ph. 07109-278414

विदर्भ की खान

प्रखर... मुखर... स्वर

● वर्ष 17 ● अंक 70 नागपुर, शनिवार, 4 फरवरी 2017 ● पृष्ठ 8 ● मूल्य ₹ 2

20% EXTRA
पाव भाजी मसाला
100/50g के पैकेट पर 20% EXTRA
SIBROCHI SPICES PVT. LTD. NAGPUR, Ph. 07109-278414

शुरू हो गया नागपुर मनपा का चुनावी दंगल

चुनावी दंगल में दबंग दिग्गजों की कटी टिकट
नामांकन के अंतिम क्षण तक मचा रहा बवाल
कांग्रेस - भाजपा में ही होगी सीधी टक्कर

नागपुर

मात्र 17 दिनों बाद होने जा रहे नागपुर महानगरपालिका के चुनावों के पूर्व शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन कांग्रेस-भाजपा सहित तमाम राजनीतिक दलों के अधिकृत उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पर चुनाव प्रशासन के समक्ष पेश कर दिये। बस इसी क्षण से अब नागपुर में चुनावी दंगल का माहौल गरमा गया है। गौरतलब है कि शुक्रवार को यहां नामांकन प्रस्तुत करने का अंतिम दिन था, वहीं उस दिन तक यानी सुबह तक किसी भी प्रमुख पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की अधिकृत घोषणा नहीं की थी। सुबह 10 बजे से दोपहर तक धीरे-धीरे एक-एक प्रभाग के उम्मीदवार फाइनल होते दिखे। दोपहर तक अपने-अपने स्तर पर सभी उम्मीदवार अपने-अपने नामांकन रूबरू व ऑनलाइन दाखिल करने की प्रक्रिया में जुटे रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद अब असली चुनावी माहौल गरमाने को आइए है और माहौल गरमाने भी लगे हैं। जैसे तो कांग्रेस-भाजपा में चुनाव लड़ने के कई इच्छुक उम्मीदवारों ने अपनी



जोश से लबरजे युवा कांग्रेसी उम्मीदवार बंटी शेलके व समर्थक।

दावेदारी पेश की थी परंतु किसी का भाग्य चमका तो अनेकों को निराशा हासिल हुई। उनकी पक्की टिकट कट गई। जिनका नामोनिशान नजर नहीं आ रहा था उन्हें भी अपने 'आकाओं' के चलते 'प्रसाद' प्राप्त हो गया। अनेक दिग्गज दावेदारों की जहां टिकट कट गई, वहीं उनके 'गॉडफादर' भी उनकी सहायता करने में हतबल दिखे। रिजेक्टेड दावेदारों का पारा सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ दिखा।

कोई पार्टी नेतृत्व को तो कोई अपने 'गॉडफादर' को खरी-खोटी सुनाता रहा। पर खेर, जिसे पार्टी का अधिकृत ए.बी. फार्म मिल गया वह फूला नहीं समा रहा था। देर शाम तक नामांकन प्रक्रिया के बाद चुनावी दंगल में दबंगों द्वारा जीत की रणनीति बनाने का जहां कार्यक्रम बनना शुरू हो गया था, वहीं बगावत के सुर भी

बड़े पैमाने पर उभरने लगे हैं। विशेषकर कांग्रेस और भाजपा में इस बार सीधी टक्कर होने की वजह से दोनों पार्टियों में ही जमकर बगावत होने के आशंका है। शुक्रवार को टिकट वितरण के पूर्व ही दोनों खेमों में जूमपैजार का पिक्चर साफ दिखाई दिया।

धूल चटाने की रणनीति

जहां पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार अपनी जीत आश्वासित करने में जुट गये हैं, वहीं जिनकी टिकट कट गई है वे भी अब डायरेक्ट-इनडायरेक्ट अधिकृत उम्मीदवार को प्रभाग में किस तरह पटकनी दे सकते हैं, इसकी व्यूह-रचना बनाने के खेल में जुट गये हैं। 'हम नहीं तो तू भी नहीं' वाली कहावत पर मंथन, विचार-विमर्श, साजिश का क्रम भी शुरू हो गया है। खेल

बिगाड़ने वालों से अधिकृत उम्मीदवारों को सावधान रहने की जरूरत होगी। चुनावी दंगल में हालांकि कौन बाजी मारेगा यह तो आज कहना जहां मुश्किल है, वहीं यह साफ है कि इस बार कांग्रेस-राकांपा और भाजपा-शिवसेना में गठबंधन नहीं होने से तथा सभी पार्टियों की 'एकला चलो रे' की भूमिका से इस बार का चुनावी दंगल काफी रोमांचक हो गया है। सत्ताधारी भाजपा के कार्यकाल को कुशासन बताकर कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाना चाहती है और लोगों से परिवर्तन की बात कर सकती है, वहीं भाजपा इस 'गढ़' को दोबारा अपने कब्जे में रखने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाएगी।

कहीं फिर गुटबाजी न ले डूबे कांग्रेस को !

कांग्रेस पार्टी की नागपुर शहर की गुटबाजी राष्ट्रीयस्तर तक लोकप्रिय है। यह पहली मर्तबा नहीं है कि कांग्रेस गुटबाजी के चलते धोखा खाती आई है। अनेकों चुनावों में कांग्रेस को यहां हार का मुंह केवल इसलिए देखा पड़ा क्योंकि यहां 'एका' नहीं है। सभी नेता 'अपनी-अपनी डफली... अपना अपना राग' अलापते हैं और अंत में धोखा खाते हैं। लगता नहीं है कि इस बार भी कांग्रेस 'एक' रहेगी।

कांग्रेस के नेताओं में गुटबाजी के चलते पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी अब मायूस हो गये हैं। उनके भी समझ से परे हो गया है कि आखिर कैसे और कब कांग्रेस के अच्छे दिन फिर लौटेंगे। इस बार मनपा पर कांग्रेस कब्जा करने में सफल हो सकती है बशर्ते पार्टी में वरिष्ठ नेतागण आपस में एक हों। आपसी खींचतानी से यह संभव होता नहीं दिखाई देता। फिर भी ये न केवल प्रकरणे कांग्रेसी नेतागण 'समझ गये' तो सत्ता हासिल कर सकते हैं...

कांग्रेस-भाजपा उम्मीदवारों की सूची अंतिम पृष्ठ पर देखें

गडकरी के हाथों में नागपुर मनपा के चुनाव की कमान

जिस प्रकार नागपुर ही नहीं बल्कि विदर्भ सहित महाराष्ट्र भर में भाजपा के हेवीवेट नेता नितिन गडकरी का अपना 'दबदबा' है, वहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक उनकी पैठ मजबूत है। फिलहाल तो नितिन गडकरी को कोई 'चैलेंज' नहीं दिखता। दरअसल उनकी कार्यशैली की ही बदौलत उनके पास यह ताकत है। पार्टी के उत्थान के लिए कई 'दियालियां' उन्होंने अंधेरे में गुजारी हैं।



नागपुर मनपा की इस बार की चुनावी कमान पूरी तरह से गडकरी के हाथों में ही है, ऐसा साफ दिखाई देता है। जिस प्रकार विगत 2-3 दिनों से उम्मीदवारों के चयन को लेकर 'वाडे' पर जो माहौल है, उससे इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि यह चुनाव भाजपा 'गडकरी स्टाइल' से ही लड़ेगी। यह भी कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि पार्टी में गडकरी के आगे सभी 'साइलेंट जोन' में चले जाते हैं। वाडे का शब्द 'अंतिम' होता है।

हर कीमत पर सत्ता हासिल करना होगा लक्ष्य

नितिन गडकरी ने जिस अंदाज में भारी मार्जिन से नागपुर लोकसभा चुनाव जीता, उससे अनेकों को उनकी स्टाइल से रूबरू होने का मौका मिला था। यह बात दीगर है कि मोदी लहर का भी साथ उन्हें मिला पर नागपुर हेडक्वार्टर पर विजयश्री से गडकरी मजबूत होकर राष्ट्रीय परिदृश्य में झलके।

संघ मुख्यालय, अपना स्वयं का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, सीएम का गृहनागर, शहर के सभी

विधायक भाजपा के (गडकरी के), जिला परिषद व निवर्तमान मनपा कर कब्जा... ऐसे में भला गडकरी आनेवाले मनपा चुनाव में कैसे भाजपा को सत्ता से दूर देखा चाहेंगे ? सूत्रों के मुताबिक तथा गडकरी वाडे के नजदीकियों से प्राप्त अंदेशों से यह साफ हो गया है कि इस बार के मनपा-चुनाव में भाजपा को हर कीमत पर सत्ता हासिल करना है। चुनावी रणनीतियों को अंजाम देने में आज 'वाडे' को कोई माल नहीं दे सकता, यह जगजाहिर है। वैसे भी गडकरी ने अपने दम पर अनेकों पार्षदों, विधायकों से लेकर सांसदों को विजयश्री का स्वाद चखाया है और उन्हें इसमें महारथ हासिल है।

नागपुर मनपा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के चयन में जिस प्रकार गडकरी इंटरस्ट ले रहे हैं उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे इस इलेक्शन को लेकर कितने सीरियस हैं। इस चुनाव को जीतना और वह भी पूरे आंकड़ों व बहुमत के साथ, यह गडकरी का पुनः लक्ष्य होगा।

बीजेपी अध्यक्ष ने मेरठ में स्थगित की पदयात्रा अखिलेश-राहुल पर जमकर बरसे अमित शाह



नई दिल्ली

भाजपा के वोटों को समेकित करने के उद्देश्य से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को मेरठ में अपनी पदयात्रा एक व्यापारी की हत्या के विरोध में स्थगित कर दी। हालांकि, अमित शाह ने मेरठ में जनसंपर्क अभियान किया और इस दौरान अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि राहुल और अखिलेश लोगों को मुर्दबंद कर रहे हैं।

रोकने का ऐलान किया। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश और राहुल मिलकर यूपी को धोखा दे रहे हैं। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। उन्होंने कहा कि एक बेटे ने देश को लूटा और दूसरे ने प्रदेश को। यूपी में भू माफियाओं ने जमीनों पर कब्जे किए हैं। यूपी में सपा, बसपा ने विकास नहीं किया। अखिलेश सरकार में कानून व्यवस्था बहुत खराब हो गई। अमित शाह ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दोनों शहजादे (अखिलेश यादव और राहुल गांधी) प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इसमें वो दोनों अभिषेक की हत्या पर जवाब दें।

आगर ये इस हत्या का जवाब नहीं देते हैं तो यूपी की जनता इन्हें सबक सिखाए। शाह ने कहा कि उत्तरप्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे बड़ी समस्या है। यूपी में हर दिन हत्या, बलात्कार की घटनाएं होती रहती हैं। प्रदेश में अपराध का ग्राफ बहुत बढ़ गया है।

बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ रही है। यूपी को हम देश का नंबर एक राज्य बनाना चाहते हैं। यूपी में भी पूर्ण विकास करना चाहती है बीजेपी। हम यूपी को देश का नंबर एक राज्य बनाना चाहते हैं। ये काम सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। अमित शाह ने कारोबारी की हत्या के विरोध में अपनी पदयात्रा स्थगित कर दी। इसके बाद वे मृतक कारोबारी अभिषेक के परिवार से मिलने उनके घर भी गए। बता दें कि शनिवार को इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 फरवरी को मतदान होगा। भाजपा साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील परिचय उत्तरप्रदेश और आसपास के स्थानों में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जता रही है।

क्षेत्र की 140 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 11 और 15 फरवरी को होगा। भाजपा इस क्षेत्र को एक मजबूत वोट के तौर पर देख रही है। भाजपा उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबले में शामिल है जिसमें सपा-कांग्रेस गठबंधन और बसपा शामिल हैं। भाजपा का कहना है कि उसका मुख्य प्रतिद्वंद्वी सपा-कांग्रेस गठबंधन है, बसपा इस क्षेत्र में पारंपरिक रूप से मजबूत रही है जहां मुस्लिमों की अच्छी संख्या है।

राज्य की 27 महानगरपालिकाओं के महापौर पद के आरक्षण का ड्रा शुक्रवार को मंत्रालय में निकाला गया, जिसमें नागपुर महानगरपालिका के लिए नागपुर महानगरपालिका के लिए सर्वसाधारण प्रवर्ग से महापौर का पद महिला के लिए घोषित किया गया है।

राज्य की 27 मनापाओं के महापौर पदों का आरक्षण घोषित

नागपुर/मुंबई

राज्य की 27 महानगरपालिकाओं के महापौर पद के आरक्षण का ड्रा शुक्रवार को मंत्रालय में निकाला गया, जिसमें नागपुर महानगरपालिका के लिए नागपुर महानगरपालिका के लिए सर्वसाधारण प्रवर्ग से महापौर का पद महिला के लिए घोषित किया गया है।

नागपुर में सर्वसाधारण प्रवर्ग की महिला होगी महापौर

राज्य की 27 महानगरपालिकाओं के महापौर पद के आरक्षण का ड्रा शुक्रवार को मंत्रालय में निकाला गया, जिसमें नागपुर महानगरपालिका के लिए नागपुर महानगरपालिका के लिए सर्वसाधारण प्रवर्ग से महापौर का पद महिला के लिए घोषित किया गया है।



जाति प्रवर्ग (कुल एक), नंदेड़, वाघाला व पनवेल मनपा अनु. जाति प्रवर्ग (कुल दो), नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड व औरंगाबाद मनपा नागरिकों का पिछड़ा वर्ग (कुल तीन), मीरा-भाईंदर, जलगांव, सांगली-मिरज-कुपवाड व चंद्रपुर मनपा पिछड़ा वर्ग महिला (कुल चार), लातूर, धुले, मालेगांव, बृहन्मुंबई, भिवंडी-निजामपुर, अकोला, अहमदनगर, वसई-विरार मनपा सर्वसाधारण प्रवर्ग (कुल आठ) तथा महिला सर्वसाधारण प्रवर्ग हेतु ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर, परभणी व नागपुर महानगरपालिका का आरक्षण घोषित किया गया।

सद्भावना दिवस से राजीव गांधी का नाम हटाने पर बिफरी कांग्रेस



नई दिल्ली

कांग्रेस ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम सद्भावना दिवस कार्यक्रमों से हटाए जाने पर नरेंद्र मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस की छाया वर्मा ने शून्यकाल के दौरान राज्यसभा में यह मामला उठाया और कहा कि राजीव गांधी का नाम सद्भावना दिवस कार्यक्रमों से हटा दिया गया है। उनका समर्थन करते हुए कांग्रेस के आनंद शर्मा ने कहा कि वर्तमान शासन ऐसे लोगों को बहावा दे रहा है, जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा, राजीव गांधी इस देश के एक शहीद हैं और इस देश ने उनकी जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में घोषित किया है।

मारन बंधुओं को आरोप मुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

नई दिल्ली

एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन को आरोप मुक्त किए जाने के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि जब सरकार और जज एंजेली अपील करेंगे तब विचार होगा, सिर्फ विशेष सरकारी वकील की अर्जी काफी नहीं है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी। पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और कलानिधि मारन को सीबीआई कोर्ट ने गुरुवार को एयरसेल-मैक्सिस केस में दोनों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं चलते बरी कर दिया था। मामले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय कर रही थी। इसी फैसले के खिलाफ आज प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट का

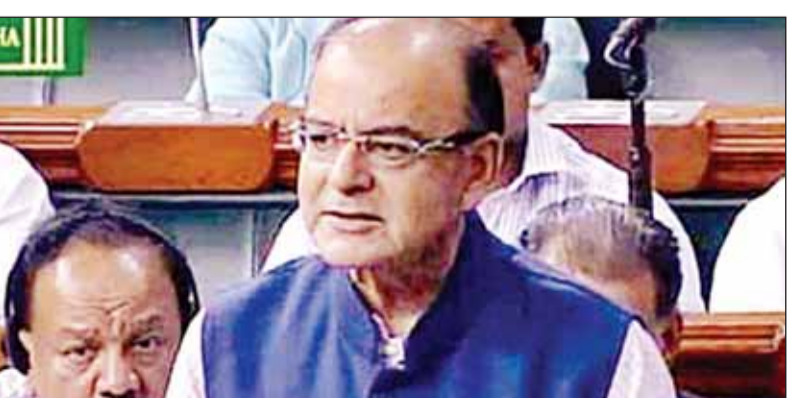


दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल इस पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि एयरसेल-मैक्सिस समझौता मामले में कुर्क की गई दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि की संपत्तियां मुक्त नहीं की जानी चाहिए।

नोटबंदी से संबंधित अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक लोकसभा में पेश

नई दिल्ली

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी से संबंधित विनिर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्वों की समाप्ति) अध्यादेश 2016 की जगह लेने वाले विधेयक को लोकसभा में पेश किया, जिसमें 31 दिसंबर 2016 के बाद पुराने 1000 और 500 रुपये के नोटों को रखने, उनका लेनदेन करने या प्राप्त करने को प्रतिबंधित किया गया है। वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा विधेयक पेश किये जाने से पहले तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सौगत राय ने विधेयक पर विरोध दर्ज कराते हुए कहा, यह विधेयक गैरकानूनी है। हालांकि जेटली ने संसद की कार्यवाही संचालन के नियम के तहत तृणमूल सांसद सौगत राय के विधेयक का विरोध करने के आधार पर ही सवाल खड़ा किया और कहा कि किसी विधेयक का उसकी विधायी क्षमता या उसके असंवैधानिक होने के आधार पर ही विरोध किया जा सकता है। दोनों आधारों पर उनकी (राय की) यह दलील कहीं नहीं ठहरती है। वित्तमंत्री ने कहा कि तृणमूल सदस्य केवल यह



कहकर विरोध नहीं कर सकते कि विधेयक सही नहीं है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में यह कहा गया है कि संसद सत्र में नहीं होने के कारण यह विधान लाना आवश्यक हो गया था। इसलिए राष्ट्रपति द्वारा बैंक नोटों में दायित्वों को समाप्त करने के लिए 31 दिसंबर 2016 को विनिर्दिष्ट बैंक नोट

(दायित्वों की समाप्ति) अध्यादेश 2016 को मंजूरी दी गई थी। विधेयक में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति 31 दिसंबर 2016 के नियत दिन के बाद से विनिर्दिष्ट बैंक नोट यानी 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को नहीं रखेगा, अंतरित या प्राप्त नहीं करेगा।

विधेयक में इस धारा का उल्लंघन करने वालों पर 10,000 रुपये का जुर्माना या उल्लंघन करते हुए रखे गये विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के अंकित मूल्य की रकम के पांच गुना, जो भी ज्यादा हो अदा करने का दंडनीय प्रावधान है। विधेयक के अनुसार, अंकित मूल्य का विचार किये बिना कुल दस नोटों से अधिक नहीं रखने वालों और अध्ययन, अनुसंधान या मुद्राशास्त्र के लिए प्रयोजनों के लिए 25 नोटों से अधिक नहीं रखने वालों पर यह दंडनीय प्रावधान लागू नहीं होगा। वित्तमंत्री ने कहा कि नोटबंदी की अधिसूचना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का धारा 26 (2) के तहत जारी की गयी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के उस समय तक प्रचलित नोटों को चयन से बाहर करने की घोषणा की थी। सदन में विधेयक पेश किये जाने के दौरान सौगत राय ने कहा कि 8 नवंबर को संसद को संज्ञान में लिये बिना प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की घोषणा कर दी जो अवैध थी। उन्होंने कहा कि यह अधिसूचना भारतीय रिजर्व बैंक को जारी करनी थी, सरकार को नहीं।